भारतीय अर्थव्यवस्था

- **प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)** – इस योजना के लक्ष्य थे शरणार्थियों का पुर्नवास, खाद्यानों के मामले में कम–से– कम सम्भव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और मुद्रास्फिति पर नियन्त्रण करना। इसके साथ साथ इस योजना में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया आरम्भ की गयी, जिससे राष्ट्रीय आय के लगातार बढने का आश्वासन दिया जा सके । इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गयी ।
- **द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)** – प्रो0 पी0 सी0 महालनोबिस के मॉडल पर आधारित इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकीकरण था इसके लिए भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया । इन मूल महत्व के उद्योगों अर्थात् लौह एवं इस्पात, अलौह धातुओं, भारी रसायन, भारी इंजीनियरिंग और मशीन–निर्माण उद्योगों को बढावा देने का दृढ निश्चय किया गया ।
- **तीसरी पंचवर्षीय योजना(1961-66) –** तीसरी योजना ने अपना लक्ष्य आत्मनिर्भर एवं स्वयं–स्फूर्ति अर्थव्यवस्था की स्थापना करना रखा है। इस योजना ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की, परन्तु इसके साथ साथ इसने बुनियादी उद्योगों के विकास पर भी पर्याप्त बल दिया जो की तीव्र आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक था ।
- **तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-67 से 1968-69)** –वर्ष 1965 में भारत–पाकिस्तान युद्ध से पैदा हुई स्थिती , दो साल तक लगातार भीषण सुखा पडने , मुद्रा का अवमुल्यन होने कीमतों में हुई वृद्धि तथा योजना उद्देश्यों के लिए संसाधनों की कमी होने के कारण चौथी योजना को अन्तिम रूप देने में देरी हुई । इसलिए इसके स्थान पर चौथी योजना के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए1966 से 1969 तक तीन वार्षिक योजनाए बायी गयी। इस अवधि को **'योजना अवकाश'(plan Holiday)** कहा गया है।
- **चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-1974)** – चौथी योजना के मूल उद्देश्य थे– स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति । चौथी योजना में राष्ट्रीय आय की 5.5प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, बाद में इसमें सामाकि न्याय के साथ विकास और 'गरीबी हटाओं' जोडा गया ।
- **पाँचवी पंचवर्षीय योजना** (1974-1985)– इसमें दो मुख्य उद्देश्यों अर्थात् गरीबी की समाप्ति और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए वृद्धि की उच्च दर को बढावा देने क अलावा आय का बेहतर वितरण और देशीय बचत दर में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की नीति अपनायी गयी । 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने चार वर्षो के पश्चात ही पांचवी योजना को समाप्त कर दिया ।
- **छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)** – छठी योजना दो बाद तैयार हो गयी । जनता पार्टी द्वारा (1978.–83 की अवधि हेतु) 'अनवरत योजना ' बनायी गयी । छठी योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र में रोजगार का विस्तार रिना, जन–उपभोग की वस्तएं तैयार करने वाले कुटीर एवं लघु उद्योंगों का बढावा देना । और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा निम्नतम आय वर्गो की आय बढाना था । परन्तु जब कांग्रेस सरकार ने नयी छठी योजना (1980–85)तैयार की, तब विकास के नेहरू मॉडल को अपनाया गय, जिसका लक्ष्य एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार करना था ।
- **सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)**– सातवीं योजना मे खाद्यानों में वृद्धि , रोजगार के क्षेत्रों का विस्तार एवं उत्पादका को बढाने वाली नीतियों एवं कार्यक्रमों पर बल देने का निश्चय किया गया ।
- **आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)** – केन्द्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण **आठवीं योजना दो वर्ष देर से प्रारम्भ हुई** आइवीं योजना का विवरण उस समय स्वीकार किया गया । जब देश एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसके मुख्य कारण थे– भुगतान संतुलन का संकट, बढता हुआ ऋण भार , लगातार बढता बजट घाटा, बढती हुई मुद्रास्फीति और उद्योग में प्रतिसार। नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक सुधारों के साथ राजकोषीय सुधोंरों की भी प्रक्रिया

जारी की ताकि अर्थव्यवस्था को एक नयी गति प्रदान की जा सके आठवीं योजना का मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलूओं में मानव विकास परना था।

- **नोंवीं परवर्षीय योजना (1997-2002)** – इसमें विकास का 15 वर्षीय परिप्रेक्ष्य शामिल किया गया। नौवीं योजना का प्रमुख लक्ष्य ' वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय और समानता' था ।
- **दसवीं। पंचवर्षीय योजना (2002-2007)** – इस योजना में पहली बार राज्यों के साथ विचार–विमर्श कर राज्यवार विकास दर निर्धारित की गयी। इसके साथ ही पहली बार आर्थिक लक्ष्यों के साथ–साथ सामाजिक लक्ष्यों पर भी निगरानी की व्यवस्था की गयी ।
- **ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)** – जीडीपी वृद्धि पर को 8 प्रतिशत से बढाकर 10 प्रतिशत करना और इसे 12 वीं योजना के दौरान 10 प्रतिशत पर बरकरार रखना ताकि 2016–17 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया जा सके ।
- **12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017)** – 12 वीं योजना (2012–17) को राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसंबर 2012 में मंजूरी मिली । भारत की 12 वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1 अप्रेंल 2012 से हो गया है।

  12 वीं योजना के लक्ष्य निम्न है –
  - वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 8प्रतिशत (योजना के एप्रोच पेपर में यह 9 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, जिसे बाद मेकं सिंतंबर,2012 में घटाकर 8.2 प्रतिशत किया गया। जिसे योजना की संस्तुति पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने घटाकर 8 प्रतिशत कर दियाा)
  - कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत व निनिर्माण क्षेत्र में 10 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि कें लक्ष्य ।
  - योजनावधि में गैर–कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड नये अवसरों के सृजन के लक्ष्य ।
  - योजना के अंत तक निर्धनता अनुपात से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत में पूर्व आकलन की तुलना में 10 प्रतिशत बिन्दु की कमी लाने का लक्ष्य ।
  - योजना के अंत तक देश में शिशु मृत्यु दर को 25 तथा मातृत्व मृत्यू दर को 1 प्रति हजार जीवत जन्म तक लाने तथा 0–6 वर्ष के आयु वर्ग में बाल, लिंगानुपात को 950 करने का लक्ष्य ।
  - योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य ।
  - योजना के अंत तक आधारिक संरचना क्षेत्र में निवेष को बढाकर जीडीपी के 9 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य ।
  - योजना के अंत तक सभी गांवों को बारहमासी सडकों से जोडना।
  - योजना के अंत तक सभी गावों में विद्युतीकरण ।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीडेंसिटी को बढाकर 70प्रतिशत करने का लक्ष्य ।

निर्धनता और बेरोजगारी

- निर्धनता से आशय उस सामाजिक क्रिया से है। जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता । विश्व बैंक के अनुसार जिस व्यक्ति की आय 1.25 डॉलर दैनिक से कम है वह निर्धन माना जाएगा ।
- ***निर्धनता :–***

  योजना आयोग ने सितम्बर 1989 में **प्रो. डी टी लकडवाला** की अध्यक्षता में एक विशेष समूह की नियुक्ति की जिसने प्रतिव्यक्ति कैलोरी उपभोग को आधार बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति उपभोग को आधार माना । भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन श्री बी एस मिन्हास ने किया और उन्हौने 1956–57 तथा 1967–68 के बीच ग्रामों के निर्धनों के प्रतिशत में कमी होने के संकेत दिए ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 41.8प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या का 25.7 प्रतिशत भाग गरीब है।

प्रधानमत्री की आर्थिक सलाहाकार समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश तुन्दूलकर की रिपोर्ट गरीबी का आंकडा 37.2प्रतिशत बताती है।

देश में राष्ट्रीय औसत के मुकाबले सबसे ज्यादा गरीबी बिहार(53.5%)में है। देश में सबसे कम गरीबी हिमाचल प्रदेश (9.5%)में है। जिसके बाद केरल(12%) का स्थान आता है।

देश में निर्धनों की निरपेक्ष संख्या के मामले मे उतर प्रदेश सबसे उपर है। देश में निर्धनता अनुपात का आकलन योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन(NSSO)के माध्यम से किया जाता है।

बेरोजगारी :–

बेराजगारी से आशय एक ऐसी स्थिती से है। जब देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक होती है। और काम करने पर राजी भी होती है। परन्तु उन्हैं प्रचलित मजदूर दर पर कार्य नहीं मिल पाता ।

भारत में बेरोजगारी :–

1. संरचनात्मक बेरोजगारी
2. शिक्षित बेरोजगारी
3. अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी
4. मौसमी बेरोजगारी
5. घर्षणात्मक बेरोजगारी
6. खुली बेरोजगारी

प्रमुख निर्धनता निवारण एवं रोजगार कार्यक्रम

कार्यक्रम	वर्ष	उद्देश्य
सामुदायिक विकास	1952	देश/राष्ट्र का समग्र विकास
प्रधानमंत्री रोजगार योजाना (PMRY)	2 अक्टूबर 1993	उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में सात लाख लघुतर इकाइयां स्थापित करके 10 लाख से भी अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना ।
स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)	1 दिसम्बर 1997	शहरी क्षेत्रों में निर्धनता निवारण योजना ।
अन्नपर्णा योजना	19 मार्च 1989	वृद्ध नागरिकों को निशुल्क अनाज ।
समग्र आवास योजना	1999	वृहद् ग्रह योजना
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(SGSY)	1 अप्रेल 1999	सामूहिक प्रयास पर बल । सहायता प्राप्त गरीब व्यक्तिओं को 3 वर्ष में BPLके उपर लाना इसमें छ कार्यक्रमों का विलय कर दिया गया है। 1.IRDP 2. TRYSEM 3. DWCRA 4. SITRA 5. MWS 6. GKY
जनश्री बीमा योजना	10 अगस्त 2000	BPL लोगों को बीमा सुरक्षा कवच देना ।
प्रधानमत्री ग्रामोदय योजना (PMGY)	2000–01	गांवों का समग्र विकास (ग्रामीण, सडक, आवास व पेयजल आपूर्ति परियोजना)
अन्तोदय अन्न योजना	25 दिसम्बर 2000	BPL परिवारों के सर्वाधिक गरीबों को अनाज रू 2/किलो गेंहू , 3रू/किलो चावल उपलब्ध कराना
काम के बदले अनाज कार्यक्रम	जनवरी 2001	ग्रामीण क्षेत्रों के काम के बदले अनाज(गेंहु व चावल) का निशु:ल्क आवंटन ।
आश्रय बीमा योजना	जून 2001	रोजगार छूटे कर्मचारियों को सुरक्षा कवच प्रदान करना ।

कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना	1 जुलाई 2001	कृषि श्रमिकों को Licके सहयोग से सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना ।
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)	15 अगस्त 2001	रोजगार आश्वासन योजना(EAS)और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को इसमें मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन कराना व खाद्यान उपलब्ध कराना।
राष्ट्रीय राजमार्ग योजना (NHS)	15 अगस्त 2001	सुमुचित गुणवता वाले राष्ट्रीय राजमार्गो को विकसित रिने के साथ साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
शिक्षा सहयोग योजना	2001–02	BPL परिवारों के बच्चों को आठवीं से आगे की शिक्षा जारी करने हेतू आर्थिक सहायता ।
वाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना	2001	शहरी स्लम आबादी को स्वच्छ आवास उपलब्ध कराने हेतु ।
सर्वशिक्षा अभियान	200–01	6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 2010 तक आठवीं से आगे की शिक्षा जारी करने हेतु आर्थिक सहायता
संकट हरण बीमा योजना	30 सितम्बर 2001	कृषको के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना
स्वजल धारा योजना	25 दिसम्बर 2002	ग्राम पंचायतों के माध्यम से कुएं , बावडी व हैण्डपम्प लगाने की सुविधा उपलब्ध कराना ।
निर्मल भारत योजना	15 अगस्त 2002	मलिन बस्तियों में सामूदायिक शौचालयों की सुविधा का विस्तार
अंशदायी बीमा योजना	15 अगस्त 2002	10 लाख बुनकरों व शिल्पकारों को बीमा सुरक्षा ।
जनरक्षा बीमा योजना	2003–03	रू1 प्रतिदिन भुगतान से चयनित व्यक्ति का निर्धारित अस्पताल में रू 30 कराने हेतू ।
जयप्रकाश नरायण गारण्टी योजना	2002–03	देश के पिछडे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों व जरूरतमन्दों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतू ।
वन्दे मातरम् योजना	14 जनवरी 2004	गरीब व पिछडे वर्ग की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बधी सुविधाएं उपलब्ध कराना।
जननी सुरक्षा योजना	8 मार्च 2003	गर्भवती महिलाओं को शिशु जन्म तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ण कराते हुए बच्चे के जन्म पर नकद सहायता उपलब्ध कराना ।
निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना	15 अगस्त 2003	स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली त्रिस्तरीय पंचायतों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करना।
हरियाली योजना	27 जून 2003	ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन
ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम (PURA)	15 अगस्त 2003	ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत सुविधा उपलब्ध कराना
प्रधानमत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMHSY)	2003	देश के पिछडे राज्यों मकें 6 नए AIIMS अस्पतालों को स्थापित करने हेतू ।
सामाजिक सुरक्षा पायलट योजना	23 जनवरी 2004	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पारिवारिक पेंशन बीमा व चिकित्सा आदि सुविधा देना ।
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना (JNNURM)	3 दिसम्बर 2005	शहरी अवस्थापना विकास
भारत निर्माण योजना	2 फरवरी 2006	ग्रामीण अवस्थापना , सर्वागीण तथा व्यापक विकास

		योजना ।
आम आदमी बीमा योजना	2007–08	भूमि रहित ग्रामीण परिवार के मुखिया या आयर्जक व्यक्ति की बीमा योजना ।
मनरेगा(2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के रूप में प्रारम्भ)	2 अक्टूबर 2009	सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना तथा काम के बदले अनाज योजना को मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम का अधिकार देना ।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (NRDWP)	1 अप्रैल 2009	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना।
राजीव आवास योजना (RAY)	2010	भारत को अगले पांच वर्षो में स्लम मुक्त बनाना ।
मिड–डे– मील योजना (MDM)	1995	कक्षा 8 तक के बच्चों को उच्च पोषक तत्व युक्त दोपहर का भोजन उपलब्ध कराके स्कूलों में बच्चों की संख्या बढाना ।

मनरेगा (MNREGA)

- प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार, जिसमें 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी होगी ।
- 15 दिन तक रोजगार प्रदान न करने पर बेरोजगारी भता देना होगा । कार्य की अवधि 7 घण्टे होगी तथा सप्ताह में 6 दिन से अधिक नहीं होगी ।
- कार्यस्थल पर मृत्यू होने पर स्थायी अपंगता की स्थिती में केन्द्र सरकार द्वारा रू0 25000 की राशि दी जाएगी ।
- वर्ष 2012 में मिहिर शाह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसके द्वारा दी गई सिफारिशों को मनरेगा–2 नाम दिया गया मनरेगा–2 के अन्तर्गत कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने, कार्य–कुशलता में सुधार लाने व भुगतान व्यवस्था में देरी होने की समस्या से छुटकारा पाने का प्रयास किया जाएगा ।
- **नोट :–** यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 6 फरवरी 2013 को महाराष्ट्र में ठाणे जिले के पालघर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया । इसके अन्तर्गत 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों और किशोरों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जानी है

भारतीय कृषि

- वर्तमान में कृषि क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 14% का योगदान करता है। 1950–51 में यह जी0 डी0 पी0 का 55.4% था ।
- भारत में श्रम शक्ति का लगभग 52 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र से जीविका पाता है। निजी क्षेत्र का यह सबसे बडा व्यवसाय है।
- यह बहुत निराशाजनक है। कि 1951–2001के दोरान कृषि श्रमिकों का अनुपात 20% से बढकर 27% हो गया ।
- कृषि से उद्योंगों को कच्चा माल मिलता है। सूती और पटसन वस्त्र अद्योग ,चीनी, चाय ,वनस्पति तथा बागान उद्योग ये सब कृषि पर निर्भर है। हस्तकरघा बुनाई, तेल निकालना, चावल कुटना आदि बहुत से लघु और कुटीर उद्योगों को भी कृषि से कच्चा माल मिलता है।
- विनिर्माण –क्षेत्र में उत्पन्न आय का 50% इस क्षेत्र से आता है।
- भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मुख्यतः कृषि वस्तुएं ही है।
- मोटे तौर पर कुल निर्यात में कृषि वस्तुओं का अनुपात लगभग 15–20% है। तथा कृषि से बनी वस्तुओं का अनुपात 20% है।

- कृषि भारत की परिवहन–व्यवस्था का मुख्य अवलम्ब है। क्योंकि रेलवे और सडक मार्ग का अधिकांश व्यापार कृषि वस्तुओं को लाना व ले जाना है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत सकल उर्वरक उपभोग में विश्व में चौथा स्थान रखता है।
- दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है।
- हरित क्रांन्ति का सम्बन्ध कृषि क्षेत्र में उत्पादन तकनीक के सुधार एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने से है। इस क्रांन्ति का श्रेय अमेरिका के डॉ0 नॉर्मन बोरलॉग और भारत के डॉ0 एम0 एस0 स्वामीनाथन को जाता है।
- दुध के क्षेत्र में क्रान्ति उत्पन करके उत्पादकता बढाने के कार्यक्रमों को ही श्वेत क्रान्ति का नाम दिया गया। श्वेत क्रान्ति की गति को और तेज करने के उद्देश्य से "**श्वेत क्रांन्ति** "का नाम दिया गया । श्वते क्रान्ति की गति को और तेज करने के उद्देश्य से '**ऑपरेशन फ्लड**' नामक योजना आरम्भ की गयी । इस क्रान्ति का श्रेय भारत के डॉ0 वर्गीस कुरियन को जाता है।
- <u>उत्पादन संम्बधित क्रांन्तियाँ</u> –
  - **हरित**:– खाद्यान(गेंहूँ , चावल, मक्का आदि) उत्पादन
  - **काली** :– पेट्रोलियम उत्पादन
  - **सदाबहार** :– कृषि
  - **नीली** :– मछली उत्पादन
  - **भूरी** :– चमडा/गैर–परंम्परागत ईंधन/कोको उत्पादन
  - **सूनहरी** :– बाग(उद्यान) शहद उत्पादन
  - **सुनहरा रेशा**(Golden Fiber)– जूट उत्पादन
  - **सलेटी** (Grey):– खाद (उर्वरक) उत्पादन
  - **गुलाबी** :– प्याज/औषधि/झींगा उत्पादन
  - **लाल** :– मॉस/टमाटर उत्पादन
  - **वृताकार** :– आलु उत्पादन
  - **चमकीला रेशा**(Silver Fiber) :– कपास उत्पादन
  - **चमकीला** :– दुग्ध उत्पादन
  - **पीली** :– खाद्य तेल उत्पादन

भारत के प्रमुख उद्योग	
प्रमुख उद्योगों की स्थापना	
उद्योग	**आधुनिक तरीके से प्रथम कारखने का स्थापना वर्ष एवं स्थान**
सुती वस्त्र	1818, कोलकाता
जूट	1855, रिशरा(पं. बंगाल)
लोहा इस्पात	1870, कुल्टी (पं. बंगाल)
चीनी उद्योग	1900, बिहार
सीमेन्ट	1904, चैन्नई(मद्रास)
साइकिल	1918, कोलकाता
कागज	1812, सेरामपुर (पं. बंगाल)
उर्वरक	1906, तमिलनाडु

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखाने	
स्थान	**तथ्य**
राउरकेला(ओडिया)	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया । 1959 ई में उत्पादन शुरू हुआ ।
भिलाई (मध्य प्रदेश)	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया गया । 1959 ई. में उत्पादन शुरू हुआ ।
दुर्गापुर(पं. बंगाल)	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया । वर्ष 1962 ई0 में उत्पादन शुरू हुआ ।
बोकारो (झारखण्ड)	एशिया का सबसे बडा संयत्र । इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया गया । वर्ष 1973 ई में उत्पादन आरम्भ हुआ ।
बर्नपुर(पं. बंगाल)	निजी क्षेत्र संयन्त्र के राष्ट्रीयकरण द्वारा अधिगृहित यह संयन्त्र रूस की सहायता से स्थापित हुआ ।
विशाखापतनम(आन्ध्र प्रदेश)	चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 2256 करोड रूपये की सरकारी लागत से रूस की सहायता से स्थापित किया गया ।
सलेम(तमिलनाडू)	चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थापित किया गया ।
भद्रावती (कर्नाटक)	चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत किया गया ।
विजयनगर(कर्नाटक)	चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया ।

सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम	
नाम	स्थान
हिन्दूस्तान कार्बनिक रसायन लिमिटेड	रसायनी (महाराष्ट्र)
भारतीय दवा एवं औषधि लिमिटेड 1. एण्टीबायोटिक संयत्र(आई0 डी0 पी0 एल0) 2. संश्लेषित दवा परियोजना 3. सर्जरी उपकरण संयन्त्र	1.ऋषिकेश (उतराखंड) 2.हैदराबाद(आन्ध्र प्रदेश) 3. चैन्नई(महाराष्ट्र)
हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक लिमिटैड	पिम्परी(महाराष्ट्र)
हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड	अलवाय (केरल)एवं दिल्ली
भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड	नंगल(पंजाब), सिन्दरी(झारखण्ड), ट्राम्बे(महाराष्ट्र), गोरखपुर(उतर प्रदेश), नामरूप(असोम), दुर्गापुर(पश्चिम बंगाल)
भारी जल संयन्त्र	नेवेली (तमिलनाडु), नाहरकटिया(असोम), राउरकेला(ओडिसा), ट्राम्बे(महाराष्ट्र)
भारत डायनामिक्स लिमिटेड	हैदराबाद
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	जलाहाली(कर्नाटक),गाजियाबाद(उतर प्रदेश)
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	रानीपुर(हरिद्वारा, उतराखंण्ड) रामचन्द्रपुर(आन्ध्र प्रदेश), तिरूचिरापल्ली(तमिलनाडु),भोपाल(मध्यप्रदेश),
भारत हैवी प्लेट एवं वैसेल्स लिमिटेड	विशाखापतनम(Andhrapradesh)
सेन्ट्रल मशीन टूल्स	बंगलूरू

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स	चितरंजन(West Bengal)
कोचीन शिपयार्ड	कोच्चि
डीजल लोकोमोटिव वर्क्स	मरवाडीह, वाराणासी(Uttarpradesh)
गार्डेन रीच वर्कशाप लिमिटेड	कोलकाता
हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	बंगलूरू
भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड	रांची
हैवी इलेक्ट्रिकल्स(भारत)लिमिटेड	भोपाल
भारी मशीन निर्माण संयन्त्र	राँची
भारी वाहन कारखाना	अवाडी(तमिलनाडू)
हिन्दुस्तान केबल्स कारखाना	रूपनारायणपुर (West Bengal)
हिन्दूस्तान मशीन टूल्स	जलाहाली(Karnataka), बंगलूरू के समीप, पिंजौर(Haryana),हैदराबाद(Andhrapradesh),कलामसारी (केरल)
हिन्दुस्तान शिपयार्ड	विशाखापतनम एवं कोच्चि
भारतीय टेलीफोन उद्योग	बंगलूरू, नैनी (Uttarpradesh),रायबरेली(Uttarpradesh)मानकपुर, गोंडा(Uttarpradesh)
इंस्ट्रमेन्टेशन लिमिटेड	कोटा(Rajasthan), पालक्कड(Keral)
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री	पेराम्बूर(Tamilnadu), कोटकपूरा(Panjab)
भारतीय मशीन टूल निगम	अजमेर(Rajasthan)
मशीन टूल मॉडल कारखाना	अम्बरनाथ , मुम्बई
मझगाँव डॉक्स लिमिटेड	मुम्बई
खनन एवं सम्बद्ध उपकरण निगम लिमिटेड	दुर्गापुर
नाहन ढलाईखाना	सिरमौर(Himachal Pradesh)
राष्ट्रीय उपकरण कारखाना	कोलकाता
प्राग टूल्स कॉर्पोरेशन	हैदराबाद निगम लिमिटेड
तुंगभद्रा इस्पात उत्पादन लिमिटेड	तुंगभद्रा (Karnataka)
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	हैदराबाद
हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	उदयपुर(Rajasthan)
भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटैड	कोरबा(Madhypradesh),रत्नागिरी(Maharastra)
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	अग्निगुडला(Andhrapradesh),Dariba(Rajasthan), मलाजखण्ड(मध्यप्रदेश),राखा (झारखण्ड)
भारत रसोई कोयला लिमिटेड	धनबाद(Jharkhand)
भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	कोलार(Karnataka)
कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड	कोलकाता
नेवेली लिग्नाइट निगम	नेवेली(Tamilnadu)
जस्ता प्रगलक	जवार (Rajasthan)
राष्ट्रीय अखबारी कागज कारखाना लिमिटेड	नेपानगर(Assom)
भारतीय तेलशोधक लिमिटेड	बरौनी (Bihar)
कोचीन तेलशोधक कारखाना	न्यूमाटी (Assom)

कोयली तेलशोधक कारखाना	कोच्चि(keral)
भारतीय विस्फोटक कारखाना	गोमिया, हजारीबाग(Jharkhand)
हिन्दुस्तान फोटोफिल्म निर्माण कम्पनी लिमिटेड	ऊंटकमण्ड,(Tamilnadu)

नवरत्न(Navratnas)

- विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले देश के 17 सार्वजनिक उपक्रमों को सरकार ने देश के 'नवरत्नों'के रूप में मान्यता दी है।
- इन्हें 1,000 करोड रूपये तक के सौदे करने की स्वायतता भी सरकार द्वारा दी गई है।

1. नेवेली निग्नाईट कॉर्पोरेशन
2. ऑयल इंडिया लिमिटेड
3. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
4. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड(HPCL)
5. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड(BPCL)
6. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटैड(NALCO)
7. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड(HTNL)
8. भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BEL)
9. हिंदुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड(HAL)
10. पावर फाइनेंस लिमिटेड(PFC)
11. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन(NMDC)
12. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13. रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड
14. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
15. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड(EIL)
16. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(CONCOR)
17. नेशनल कस्ट्रक्शंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नोट :– कोल इंडिया लिमिटेड(CIL), भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड(SAIL), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन(IOC),तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम(ONGC), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम(NTPC), भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड(BHEL) तथा भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड(GAIL)को सरकार ने **महारत्न का दर्जा** दिया है। इससे इनके पास ज्यादा वितीय और परिचालन सम्बधी स्वायता होगी । जिससे इन्हें वैश्विक स्तर की प्रमुख कम्पनी बनने में मदद मिलेगी ।

भारतीय कर व्यवस्था

भारतीय सरकार को करों से ही समस्त राजस्व की प्राप्ति होती है।

करों के प्रकार :–

(क) **प्रत्यक्ष कर (Direct taxes)**

ऐसे कर को प्रत्यक्ष कर की संज्ञा दी जाती है। जिसकी अदायगी उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है। जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है।

- **केन्द्र सरकार** – आयकर (व्यक्तिओं, अविभाजित हिन्दु परिवारों तथा संस्थाओं की आय पर)निगम कर (कम्पनीयों की आय पर कर)धन–कर, एस्टेट ड्यूटी (सम्पदा शुल्क) उपहार–कर, व्यय कर, ब्याज– कर
- **राज्य सरकारें** – होटल प्राप्तिओं पर कर , भू–राजस्व, कृषि आय पक र , व्यवसाय–कर , गैर–शहरी अंचल सम्पतिओं पर कर, रोजगारों पर कर ।

(ख) **परोक्ष कर** (Indirect Taxes)

ऐसे करों को अप्रत्यक्ष कर की संज्ञा दी जाती है। जिन्हें दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकता है।

- **केन्द्र सरकार** – सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर, सेवा–कर ।
- **राज्य सरकारें** – बिक्री कर/व्यापार–कर, डीजल/ पेट्रोल पर बिक्री कर , स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, वस्तुओं एवं यात्रिओं पर परिवहन कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क , गन्ने की खरीद पर शुल्क तथा उपकर, प्रवेश कर, विज्ञापन रि, शिक्षा उपकर, कच्चे जूट पर कर , सट्टेबाजी पर कर ।

नोट –

- भारत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क(Excise Duty)केन्द्र सरकार के राजस्व का प्रमुख स्त्रोत है।
- राज्य सरकार के कर राजस्व में बिक्री कर (SalesTax)का हिस्सा सबसे अधिक होता है।
- भारत में आयकर प्रगामी है। अर्थात आय में वृद्धि के साथ–साथ कर में भी वृद्धि होती है।
- जीएसटी वस्तुओं व सेवाओं पर लगने वाला कर है जो हर स्तर पर वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं की अदायगी पर लगेगा । इसे राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु व सेवा पर वैट कह सकते है।

भारत में प्रतिभूति –मूद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन

भारत में प्रतिभूति मूद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है–

★ **छापेखाने (printing press)** -

1. **इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक(महाराष्ट्र)** -
   नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभुति (India Security press) में डाक सम्बन्धी लेखन सामग्री , डाक एवं डाक– भिन्न टिकटों, अदालती एवं गैर –अदालती स्टाम्पों बैंको(RBIतथाSBI)के चेंकों, बॉण्डों, राष्ट्रीय बचत पत्रों आदि के अलावा राज्य सरकारों,सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों निगमों आदि के प्रतिभुति पत्रों की छपाई की जाती है।
2. **सिक्योरिटी प्रिन्टिंग प्रेस, हैदराबाद .-**
   सिक्योरिटी प्रिन्टिंग प्रेस हैदराबाद के स्थापना दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने के लिए वर्ष 1982 में की गई थी, ताकि भारत प्रतिभुति मुद्राणालय, नासिक रोड के उत्पादन की अनुपूर्ति की जा सके ।
3. **करेन्सी नोट प्रेस ,नासिक (महाराष्ट्र)** -
   नासिक रोड स्थित करेंन्सी नोट प्रेस 10, 50, 100, 500 तथा 2000 रूपये के बैंक नोट छापती है। और उनकी पूर्ति करती है।
4. **बैंक नोट प्रेस देवास (मध्य प्रदेश) -**
   देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 10, 20, 50, 100, और 500 रू के उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखाना प्रतिभुति पत्रों की स्याही का निर्माण भी करता है।
5. **साल्बोनी(प0बंगाल) तथा मैसूर (कर्नाटक) के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मूद्रण लिमिटेड -**
   दो नयी एवं अत्याधुनिक करेंन्सी नोट प्रेस मैसूर(कर्नाटक) तथा साल्बोनी(प0बंगाल) में स्थापित की गयी है। यहाँभारतीय रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में करेन्सी नोट छापे जाते है। इन नए मुद्रणालयों में 1998–99 तक 10,000 मिलियन करेन्सी नोटों का अतिरिक्त वार्षिक मुद्रण का अनुमान था। देवास तथा नासिक रोड स्थित करेंन्सी नोट प्रेसों में प्रतिवर्ष 6,000 मिलियन करेन्सी नोटों का मुद्रण होता है।

6. **सिक्योरिटी पेपर मिल,होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)** -
बैंक और करेन्सी नोट कागज तथा नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में 1967–68 में चालु की गई थी ।

***टकसाल* (Mints)**

★ सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की पांच टकसालें मुम्बई, कोलकाता, चेर्लापल्ली, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित है। मुम्बई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें काफी समय पहले क्रमशः 1830, 1903 और 1950 में स्थापित की गई। जबकि नोएडा की टकसाल 1989 में स्थापित की गई थी । मुम्बई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों (मेडल) का भी उत्पादन किया जाता है।

भारतीय बैंकिंग

- बैंक ऑफ हिन्दुस्तान (1770ई.) यूरोपिन प्रबन्धन में भारत का पहला बैंक था। भारत में पहला भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। जिसकी स्थापना वर्ष 1881 में की गयी थी ।

भारतीय रिजर्व बैंक –

- भारत का केन्द्रीय बैंक
- 1 अप्रेल 1935 को 5 करोड रूपये की अधिकृत पूंजी के साथ स्थापना
- 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण । रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुम्बई में है।
- केन्द्रीय बोर्ड के अतिरिक्त RBI के चार स्थानीय बोर्ड भी है। जिनके मुख्यालय मुम्बई, कोलकाता ,चैन्नई तथा नई दिल्ली में है।
- वर्तमान समय में RBI करेन्सी नोट जारी करने के लिए न्यूनतम निधि(Minimum Reserve System)अपनाता है। इस पद्धति में RBI के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड रूपये के मूल्य से कम नहीं होने चाहिए । जिसमें से न्यूनतम 115 करोड का स्वर्ण होना आवश्यक है।

भारतीय स्टेट बैंक –

- 1921 तीन प्रेसीडेंसी बैंकों(बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास) को मिलाकर इम्पीरियल बैंक की स्थापना की गयी। वर्ष 1955 में इसका नाम बदलकर **भारतीय स्टेट बैंक** (SBI)रख दिया गया ।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बडा बैंक है।
- वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक समूह की 21,500 से ज्यादा शाखाएं कार्य कर रही है।
- SBI के राष्ट्रीयकरण के समय इसके साथ अन्य 8 बैंको(वर्तमान में केवल 5) को SBI के सहायक बैंक (Associate Bank) के रूप में बदल दिया गया था। और इसे स्टेट बैंक समूह(State Bank Group) का नाम दिया गया ।
- वर्तमान में स्टेट बैंक के सहायक बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टैट बैंक ऑफ मैसूर तथा स्टेट बैंक ऑफ ट्रॉवणकोर शामिल है।
- स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्रको SBI में वर्ष 208 में तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को SBI में वर्ष 2010 में विलय किया गया ।

व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण –

- बैंकों कों राष्ट्रीय नियोजन की मुख्य धारा से जोडने के उद्देश्य से सरकार ने 19 जुलाई 1969 को 14 बडे व्यापारिक बैंकों (जिनकी जमाएं 50 करोडरूपये से अधिक थी) का राष्ट्रीयकरण कर दिया ।

ये बैंक थे –

सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ,पंजाब नेशनल बैंक ,बैंक ऑफ इण्डिया, युनाइटेड कमर्शियल बैंक, सिण्डीकेट बैंक , केनरा बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इण्डियन बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र

- पुनः 15 अप्रैल,1980 को सरकार ने 6 बडे व्यापारिक बैंकों (जिनकी जमाएं200 करोड रूपये से अधिक थी)को राष्ट्रीयकरण कर दिया –

आन्ध्रा बैंक, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इण्डिया , विजया बैंक , औरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स , कॉर्पोरेशन बैंक

- वर्तमान में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की कुल संख्या 21 से घटकर 20 रह गई, क्योंकि 4 सितम्बर 19923 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इण्डिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया ।
- **अन्य बैंक एवं वितीय संस्थाएँ–**

बैंक का नाम	स्थापना वर्ष	उद्देश्य /प्रमुख कार्य
भारतीय औद्योगिक ऋण व विनियोग निगम बैंक (ICICI)	जनवरी 1955	औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देना एवं सहायता करना
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक(IDBI)	जुलाई, 1964	दीर्घकालीन औद्योगिक वित प्रदान करना ।
राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक(NABARD)	जुलाई, 1982	ग्रामीण साख प्रदान करने वाला शीर्ष बैंक
भारतीय निर्यात –आयात बैंक(EXIM BANK)	जनवरी 1982	विदेश व्यापार से सम्बद्ध कम्पनियों को वितीय सहायता व सुविधाएं प्रदान करना ।
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (IRBI)	मार्च 1985	बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनरूद्धार के लिए वित मुहैया करना ।
राष्ट्रय आवास बैंक (NHB)	जुलाई 1988	आवास बनाने एवं सम्पति के विकास के लिए वित प्रदान करना, गंदी बस्तियों का पुनर्विकास आदि ।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	अप्रैल 1990	लघु क्षेत्र के उद्योगों का विकास व सम्बर्द्धन

महत्वपूर्ण बैंकिंग दरें :–

- **बैक दर(Bank Rate)** – बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है। जिस पर केंन्द्रीय बैंक(RBI) अपने सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है। अथवा स्वीकार्य प्रतिभुतियों पर ऋण देता है। बैंक दर में परिर्वतन करके केन्द्रीय बैंक साख की मात्रा को प्रभावित कर सकता है।
- **रेपो दर (Repo Rate)** - रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बॉण्डों एवं प्रतिभूतियों (पुनर्खरीद समझोतों के अन्तर्गत) पर दी जाने वाली ब्याज की दर **रेपो दर** कहलाती है।
- **रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)** – यह रेपो दर से उल्टी होती है। बैंको के पास दिनभर के कामकाज के बाद बहुत बार एक बडी रकम शेष बच जाती है। बैंक वह रकम अपने पास रखने के बजाए रिजर्व बैंक में रख सकते है। जिस पर उन्हें रिजर्व बैंक से ब्याज भी मिलता है। जिस दर पर यह ब्याज मिलता है। उसे रिवर्स रेपो दर कहते है।
- **नगद आरक्षण अनुपात(Cash Reserve Ratio)** – प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपनी कुछ जमाओं का एक निर्धारित प्रतिशत भाग अपने पास सदैव नकद रूप में रखता है। जिसे नकद आरक्षण अनुपात(CRR) कहते है।
- **वैधानिक तरलता अनुपात** (Statutory Liquidity Ratio)– बैंकों को अपनी जमाराशियों का कुछ प्रतिशत प्रतिभुनियों के रूप में रखना होता है। इस दर को ही वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)कहा जाता है।

भारतीय शेयर बाजार

- शेयरों और अंश पत्रों का क्रय–विक्रय जिस बाजार में होता है। उसे शेयर बाजार कहा जाता है।
- ये शेयर बाजार कुछ निश्चित एवं नियत स्थानों पर ही होते है। जिन्हें स्टॉक एक्सचेन्ज के नाम से जाना जाता है।
- पब्लिक इश्यू जारी करके संसाधन एकत्रित करने वाली कम्पनियों को यहाँ पंजीकरण कराना होता है।
- हमारे देश में कुल 24 स्टॉक एक्सचेन्ज है। जिनमें लगभग 7000 कम्पनियों के शेयर सूचीबद्ध है। देश का सबसे पुराना एक्सचेन्ज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है।
- भारतीय प्रतिभुति एवं एक्सचेंज बोर्ड(सेबी) की स्थापना 1988 में एक्सचैजों की कार्य पद्धति पर निगरानी रखने हेतु हुई थी ।

बीमा उद्योग –

- भारत की प्रथम जवन बीमा कम्पनी ओरिएण्टल सोसायटी (1818) थी

- भारतीय जीवन बीमा निगम(LIC) की स्थापना 1 सितम्बर 1956 को हुई थी ।
- इसके सात क्षेत्रीय कार्यालय है। जबकि इसका केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई में स्थित है।
- भारतीय साधारण बीमा निगम(GIC)ने 1 जनवरी, 1973 से काम करना प्रारम्भ किया । इसकी चार सहायक कम्पनियाँ है। 1.नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 2. न्यू इण्डिया कम्पनी लिमिटेड 3. ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटैड 4. यूनाइटैड इण्डिया इन्श्योरेस कम्पनी लिमिटेड
- बीमा क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।